प्रतिस्थापन, बेहतर प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन, निर्यात से उपार्जन संतुलित क्षेत्रीय विकास आदि पर जोर दिया जाता है। 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाली वृहत परियोजनाओं से 12% और उससे अधिक वित्तीय प्रतिफल दर तथा आंतरिक आर्थिक प्रतिफल दर प्राप्त करने की आशा की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Rehabilitation of Rohtas Industries Limited

4700. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what amount of fund was provided by the Central Government to Rohtas Industries Limited of Dalmianagar for its rehabilitation;

(b) what is its financial position at present;

(c) whether all its four units are fully operational;

(d) the number of workers who were rendered jobless because of closure and have been employed back and how many of them are yet to be called to work; and

(e) whether there are some serious complaints pending against the rehabilitation commissioner, if so, what steps are being taken by Government to meet these complaints?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Rupees, Fourteen crores as loan and Rupees six crores as grant were provided for rehabilitation of Rohtas Industries Ltd., Dalmianagar, Rohtas, by the Government of India.

(b) The details of the financial position are given in the statement enclosed. (See below)

(c) Excepting the paper unit, other three units, namely the Vanaspati, Asbestos, and Cement units are in commercial production.

(d) 13,523 workers were affected by the closures, of which 4,197 have been re-employed and 9,326 are yet to be called to work.

(e) The State Government of Bihar is enquiring into complaints received against the Rehabilitation Commissioner.

Statement

Rehabilitation of Rohtas Industries Limited

As per Reports, submitted to the State Government by Rehabilitation Commissioner, Rohtas Industries Limited, the Provisional and Unaudited Statement of Receipts and Payments for rehabilitation and operation of different units of Rohtas Industries Limited as on 16th July, 1992 is as below:

Amount

(Rs. in lakh)

A. *Receipts*	
(a) From Government (Government of India & Government of Bihar)	3,000.36
(b) Interest from Bank	265.13

(c) *Sales Proceeds*

1. Vanaspati Division	2,169.17	
2. Asbestos Division	689.44	
3. Steel Foundry Division	75.51	
		2,934.12
TOTAL RECEIPTS		6,190,61
B. Payments		6,158.49
C. Balance (in Bank)		32.12
D. Balance (Raw materials & Finished goods)		814.55
E. Sales Tax Liabilities		131.90

सवाई माधोपुर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किया जाना

4701. **श्री मूलचंद मीणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन्ही जिलों में उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के लिए उन्हें पिछड़े जिलों के रूप में घोषित करने के लिए क्या-क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) राजस्थान में सवाई माधोपुर जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला होने के बावजूद, इसे पिछड़ा जिला घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त जिले मे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसे कब तक एक पिछड़े जिले के रूप में घोषित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पिछड़ा जिला घोषित करने के लिए निर्धारित मानदंड ये थे-- प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल का उत्पादन जो इस पर निर्भर है कि क्या जिला खाद्यान्न नकदी फसल बहुल है, आबादी में कृषि कामगारों का अनुपात, प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, प्रति लाख आबादी में कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा वैकल्पिक रूप से प्रतिलाख आबादी में दूसरे व तीसरे प्रकार के कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, आबादी के अनुपात में पक्की (सरफेस्ड) सड़कों की लंबाई अथवा आबादी की तुलना में रेलवे मील दूरी।

(ख) राजस्थान में सवाईमाधोपुर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया गया था क्योंकि उसने उक्त प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया था।

(ग) इस समय किन्हीं और जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Manufacturing of light Trainer aircraft SWATI

4702. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether production licence was given to BHEL to manufacture light trainer aircraft SWATI (LT-I); and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Yes,